भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2613
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

†2613.श्रीमती शांभवीः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री राजेश वर्माः
श्री अरुण भारतीः
श्री अतुल गर्गः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-2026 के दौरान बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में सहकारिता क्षेत्र में कार्यान्वित विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना नामक परियोजना की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उन पैक्स की कुल संख्या कितनी है, जहां गत एक वर्ष के दौरान विकेंद्रीकृत गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) और उचित मूल्य की दुकानों का सक्रिय रूप से निर्माण किया जा रहा है या उन्हें चालू कर दिया गया है;

(ग) बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उक्त सहकारी भंडारण इकाइयों की सहायता हेतु कृषि एवं खाद्य वितरण योजनाओं से जारी की गई कुल केंद्रीय वित्तीय अभिसरण निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थानीय समितियों द्वारा उक्त भंडारण सुविधाओं के निर्माण के दौरान भूमि आवंटन या संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उक्त पैक्स-संचालित गोदामों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद प्रणाली के साथ एकीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि उसके पास अधिशेष भंडारण क्षमता है, इसलिए वह सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत भाग नहीं ले रहा है । तथापि, राज्य के बालाघाट जिले में परसवाड़ा समिति में एक गोदाम का निर्माण किया गया था।

(ख): बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अब तक विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर तथा उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शॉप) निर्मित/संचालित करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की कुल संख्या का विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

(ग): कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना के अंतर्गत बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सहकारी भंडारण इकाइयों के समर्थन हेतु जारी की गई अनुदान (सब्सिडी) राशि का विवरण **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है। एएमआई के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को कोई सब्सिडी जारी नहीं की गई है ।

(घ): सहकारिता क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत पात्र सहकारी समितियाँ, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) भी शामिल हैं, अपनी स्वामित्व वाली भूमि अथवा पट्टे (लीज़) पर उपलब्ध भूमि पर अवसंरचना की स्थापना कर सकती हैं। आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराने में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी भंडारण अवसंरचनाओं का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों तथा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के विनिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों से अब तक भंडारण अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.): योजना के अंतर्गत निर्मित गोदामों का पंजीकरण भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाता है। पात्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तथा अन्य सहकारी समितियों का WDRA के साथ पंजीकरण कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि वे आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद (e-NWR) प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकें। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य भी WDRA की e-NWR प्रणाली की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

******

अनुलग्नक- क

स्वीकृत, निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	निर्मित गोदामों की संख्या	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	117	117	-
2.	बिहार	36	-	5
3.	उत्तर प्रदेश	14	1	-
4.	मध्य प्रदेश	1	1	-
कुल		**168**	**119**	**5**

अनुलग्नक- ख

क्रम सं.	राज्य का नाम	पैक्स		
		गोदाम	कस्टम हायरिंग सेंटर	उचित मूल्य की दुकानें
1	आंध्र प्रदेश	685	6	71
2	बिहार	5828	2659	3752
3	मध्य प्रदेश	2032	87	4012
4	उत्तर प्रदेश	1862	169	212

अनुलग्नक- ग

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल अग्रिम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	25	5.06
2	मध्य प्रदेश	1	0.13
3	उत्तर प्रदेश	1	0.05